इस तरह से बिल्कुल देश को खत्म करती जाना चाहती है और देश को खत्म करने वाले तरीकों को ही अपनाती रहेगी, उनको ही चलाती रहेगी ?

अध्यक्ष महोदय : नैक्स्ट क्वेश्चन, डा० राम मनोहर लोहिया ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मुझी को मेरे हाथों से मारेंगे आप ?

अध्यक्ष महोदय, आप खुद सोचें । जो सवाल होते हैं उनका जवाब तो आप दिलाया करें । अगर जवाब नहीं दिलवायेंगे तो ये मंत्री लोग तो जो चाहेंगे, कर लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : नैक्स्ट क्वैश्चन ।

Role of Panchayati Raj in Education

+

*33. **Dr. Ram Manohar Lohia:**
Shri Bagri:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Maurya:
Shri Madhu Limaye:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1358 on the 26th April, 1966 and state:

(a) whether the Education Commission has since submitted its recommendations on the role of Panchayati Raj Institutions in the field of education;

(b) if so, the main outlines thereof; and

(c) the action taken by Government thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-6463/66].

(c) The recommendations are under consideration of Government.

डा० राम मनोहर लोहिया : क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि पंचायतों के प्रतिनिधि लोग तो अधिकतर पिछड़ी और छोटी जातियों के होते हैं और सरकारी नौकर अधिकतर ऊंची जातियों के होते हैं और इसके कारण से जो असन्तुलन होता है या तोड़ होती है उससे द्वेष पैदा होता है और शिक्षा की पद्धति बिगड़ती है ? अगर ध्यान दिया है तो इसके बारे में सरकार ने क्या तरीका निकाला है ?

Shri Shinde: I do not agree with the submission made by the hon. Member. In fact, in Rajasthan a Committee went into this problem and that Committee noted with satisfaction that the transfer of primary education to panchayat samities has resulted in improvement of attendance of teachers, regular and proper disbursement of salaries, greater awakening of the public to the importance of primary education etc.

श्री रामसेवक यादव : असत्य बात कह रहे हैं । इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Shinde: But I may submit that this question deals with the Report of the Education Commission. It has recently been received and it would be taken into consideration by the Education Ministry. We are only concerned with the role of panchayati raj on this subject.

डा० राम मनोहर लोहिया : आप समझते हैं कि सवाल का जवाब आ गया है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि अभी रिपोर्ट आई है और वह कंसिडर हो रही है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : फिर आप सवाल करने क्यों देते हैं कोई जवाब नहीं देते हैं ये मंत्री लोग कुछ तो जवाब दिया करें।

अध्यक्ष महोदय : अब आप दूसरा सवाल करें।

डा० राम मनोहर लोहिया : दूसरा सवाल कर देता हूं गैर-जरूरी काम तो हो ही रहा है। दूसरा सवाल आपको ही सुना देता हूं। आप ही उसको सुन लें।

श्री म० ला० द्विवेदी : आप मंत्री हो जायेंगे।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप लें गे. के रहते हुए हम मंत्री होंगे? आपका जमाना खत्म हो गया है आप लें.गों के लदने के दिन आ गए हैं।

क्या पंचायती राज के बहुत कुछ महकमों को इसलिए खोला गया है कि सरकार के लोग अपने रिश्तेदारों या आसपास के लोगों को नौकरियां दे सकें अथवा इसलिए कि जनता के अन्दर पढ़ेलिखे जो बेकार होते हैं उनको रख कर उनके अन्दर व्याप्त असन्तोष को रोक सकें। किस लिए ये सब महकमे खोले गए हैं?

Shri Shinde: The hon. Member is aware that Panchayati Raj has been introduced as a result of the principle which has been incorporated in our Constitution itself in article 40 and in many States the appointment of teachers is entrusted to impartial bodies. I do not think the contention of the hon. Member that patronage is being provided is correct.

श्री मौर्य : देहातों में बसने वाले जो लोग हैं उनमें ज्यादातर तादाद अछूत कहे जाने वाले या पिछड़ी समाज जिसको कहा जाता है, उन लोगों की होती है। क्या सरकार ने कोई ऐसे आंकड़े निकाले हैं कि देहातों में बसने वाले पिछड़े समाज और अछूत कहे जाने वाले लोगों में शिक्षा का कितना अनुपात है, किस अनुपात से उन लोगों में लोग शिक्षित हैं और वह अनुपात देश के अन्य लोगों के मुकाबले में कितना कम है? यदि वह बहुत कम है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या यत्न सरकार कर रही है?

Shri Shinde: This question should be addressed to the Education Ministry, but I may submit for the information of the hon. Member that we are equally seized of the matter. As far as education of lower castes and communities is concerned, everywhere effective steps are being taken to see that necessary facilities are provided for educating them.

श्री मौर्य : पहला तो मेरा एतराज यह है कि देहातों में शिक्षा देने के प्रश्न पर यह प्रश्न है। यह सीधा सादा सम्बन्ध रखता है पंचायती राज से। आप इसको शिक्षा मंत्रालय पर नहीं टाल सकते हैं, अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। कितने प्रतिशत उन लोगों में से जोकि देहातों मे बसते हैं और जो पिछड़ी जातियों के हैं शिक्षित हैं और यदि उनकी संख्या बहुत ही कम है, और देश के और लोगों के मुकाबले में वह बहुत गिरे हुए हैं तो उनको ऊपर लाने के लिए तथा उनमें शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाने के लिए आप क्या यत्न कर रहे हैं?

Shri Shinde: As far as the figures are concerned, we have not got the figures with us at the moment.

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : देश में शिक्षा का विस्तार बहुत ही कम है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा आयोग ने पंचायती मंत्रालय से इस संबंध में भी क्या विचार विमर्श किया था कि किस तरीके से पंचायती राज इस देश के अन्दर शिक्षा का विस्तार करने में पूरा-पूरा योगदान दे सकता है?

Shri Shinde: At that time the Ministry of Community Development and Co-operation was a separate entity and the Education Ministry did afford us an opportunity to submit our say on behalf of the CD Ministry to the Education Commission.

श्री किशन पटनायक: अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझ से न पूछें।

श्री किशन पटनायक : पिछले दोनों सवालों पर मैं बार-बार खड़ा हुआ हूं और आपने मुझे नहीं बुलाया। अब मैं बैठा था आपने मुझे बुला लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रश्न करने के लिए बुलाने का क्या तरीका . . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल करें। मेरे पास तरीका नहीं है।

श्री किशन पटनायक : मेरा सवाल यह है कि प्राइमरी शिक्षा पर कुल कितना खर्च होता है और उसका कितने प्रतिशत पंचायती राज के जरिये होता है तथा जितने लड़के प्राइमरी स्कूलों में हैं उनमें से कितने प्रतिशत अभी पंचायतों के अधीन पढ़ रहे हैं?

Shri Shinde: I think, a notice will be required for this question and the hon. Member may be advised to address this question to the Education Ministry.

Shri D. C. Sharma: Is the Government aware of the fact that at all educational gatherings, including the all-India conference which was held recently at Allahabad, there has been a unanimous view that education should be taken away from the purview of panchayati raj because it has led to deterioration of standards, nepotism, wrongful transfers and non-payment of salaries at proper time, if so, will the Government take away education from panchayati raj and give it some other toy to play with?

Shri Shinde: As I have already mentioned and submitted, the recommendations of the Education Commission have recently been received and one of the subjects under consideration is as to what should be the role of panchayati raj. That will be taken into consideration by Government.

श्री सरजू पाण्डेय : आम तौर से प्राइमरी शिक्षा के जो स्कूल हैं वे या तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चलाते हैं या प्राइवेट हाथों में हैं सभी जगह लोग अपने रिश्तेदारों को टीचर्स के तौर पर रख लेते हैं। तमाम शिक्षा शास्त्रियों की देश में यह मांग है कि शिक्षा को प्राइवेट हाथों से निकाल कर सरकार अपने हाथ में ले ले। मंत्री महोदय ने उलटा कहा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सब की जांच कराने के लिए सरकार फिर से कोई कमेटी बिठायेगी ताकि सही स्थिति का पता लगाया जा सके?

Shri Shinde: All these matters are under consideration and they form part of the Commission's Report.

श्री रामसेवक यादव : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सरकार का ध्यान इस ओर भी खींचा है कि पंचायती राज के अन्तर्गत बच्चों को जो तालीम, प्रारम्भिक शिक्षा, दी जाती है, उसमें और पब्लिक स्कूलों के जरिये दी जाने वाली शिक्षा में बहुत बड़ी असमानता है—पंचायती राज के अन्तर्गत प्रति-लड़का एक रुपया खर्च होता है, जब कि पब्लिक स्कूलों में प्रति-लड़का पचास साठ रुपये से ज्यादा खर्च होता है—; यदि हां, तो क्या उस ने इस असमंजस्य को दूर करने के लिए कोई सुझाव दिया है।

श्री म० ला० द्विवेदी : यह प्रश्न शिक्षा मंत्रालय का है।

Shri Shinde: The Commission's Report has not still been printed. That

has not been circulated to various Ministries. I think the Education Ministry will take into consideration all these matters.

श्री काशी राम गुप्त : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में जिला परिषदों के प्रमुख उस कमीशन के सदस्य होते हैं, जो अध्यापकों आदि की पंचायत राज की नौकरियों में नियुक्तियां करता है और सत्ताधारी दल ऐसे लोगों के लड़कों और लड़कियों को नौकरियां दे रहा है, जिनका उपयोग वह आम चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए, उन की हिमायत और पक्षपात प्राप्त करने के लिए कर सके ; यदि हां, तो सरकार इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाना चाहती है ?

The Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri C. Subramaniam): I respectfully submit education, particularly, elementary education and all those things is a State subject. We come in for purposes of coordination and laying down general policies. The Education Commission has made certain recommendations. Now, as to what happened in a particular State with regard to the transfer of teachers and other things, certainly, we cannot go into it. It is a matter which should be raised in the Legislative Assembly of the State.

श्री काशी राम गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब कहते हैं कि यह स्टेट सबजेक्ट है ।

श्री काशी राम गुप्त : ये लोग पंचायती राज का अंग हैं । जो लोग ऐसा काम करते हैं, उनके बारे में क्या किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका जवाब दे दिया है ।

983 (Ai) LSD—2.

खाद्यान्न के लाने-ले जाने पर प्रतिबन्ध

+

*34. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री रा० बरुआ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री राम सहाय पांडेय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री उमानाथ :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर खाद्यान्न को लाने ले जाने पर लगे हुए प्रतिबन्धों को हटाने के लिये सरकार द्वारा कोई निर्णय किया गया है या किये जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका मोटा ब्यौरा क्या है ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) The question of removal of restrictions on the movement of foodgrains will be considered on receipt of the report of the Foodgrains Policy Committee.